

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शो,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 03 सितम्बर 2007

विषय: गोपेश्वर, जिला चमोली में न्यायिक अधिकारियों के श्रेणी-IV के तीन आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-500/यू०एच०सी०/एडमिन(बो)/निर्माण/2006, दिनांक 20.2.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-84-दो(1)/सुत्तीस(1)/न्या.अनु./2004, दिनांक 21.12.2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गोपेश्वर, जिला चमोली में न्यायिक अधिकारियों के श्रेणी-IV के तीन आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदित लागत रुपये 39,85,000/- के सापेक्ष पुनरोक्षित रु० 67,49,000/- (सहस्र छह लाख उन्चास हजार रुपये मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में पुनरोक्षित लागत के विरुद्ध अवशेष अतिरिक्त धनराशि रु० 27,64,000/- (सत्ताइस लाख चौसठ हजार रुपये मात्र) का व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विरलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदुपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) इस धनराशि के पूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाय ।
- (3) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदुपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (4) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरोक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (5) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय ।
- (6) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि का मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

- (7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भू-भौतिक निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय।
- (8) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उन्हीं मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
- (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- (10) निर्माण कार्य कराने समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासन-आदेश संख्या 2047/XIV/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टार पर्चेज रूलस, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपक्षोभिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-00-आयोजनागत-03-न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण-24-बृहत् निर्माण कार्य" के नाम से ढाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-824/XXVII(5)/2007, दिनांक 29.8.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( आर०डी०पालीवाल )  
सचिव।

संख्या-33-डी(8)/XXXVI(1)(2)/2007-133-डी/02-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिला न्यायाधीश, चमोली।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
7. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( क०पी०पाटनी )  
अनु सचिव।